

पंजाब में बाढ़ का विकराल रूप, 43 लोगों की मौत

♦आप सांसद ने मदद के लिए दिए 5 करोड़

♦केंद्र से मांगा दस हजार करोड़ का राहत पैकेज

पंजाब, 05 सितम्बर। आम आदमी पार्टी (अअप) के राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने पंजाब के बाढ़ राहत कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपये देने का वादा किया है। इसके लिए उन्होंने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (टडछअज) के तहत आवंटित राशि और अपने निजी योगदान से धन जुटाया है। साहनी ने घोषणा की कि इस राशि का एक हिस्सा उन्नत बचाव नौकाओं, आधुनिक गाद निकालने वाली मशीनों और भविष्य में आने वाली आपदाओं से संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए टटबंधों के निर्माण पर खर्च

किया जाएगा। अपने गैर-सरकारी संगठन, सन फाउंडेशन के माध्यम से, साहनी पहले ही मोटरबोट, एम्बुलेंस, सूखा राशन किट, चिकित्सा आपूर्ति, स्वच्छता सामग्री और पशुओं के चारे पर 1 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर चुके हैं। उन्होंने अगले बुवाई चक्र के लिए सीमांत किसानों को उर्वरक, बीज और कीटनाशक उपलब्ध कराने का भी आश्वासन दिया। केंद्रीय सहायता का आग्रह करते हुए, साहनी ने 10,000 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की मांग की, जिसमें फसल नुकसान का सामना कर रहे किसानों के लिए 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजे के साथ-साथ दिहाड़ी मजदूरों और पशुपालकों के लिए आर्थिक सहायता का प्रस्ताव रखा गया।



पंजाब में प्रशासन हाई अलर्ट पर है क्योंकि भाखड़ा बांध का जलस्तर 1,679 फीट तक पहुँच गया है, जो इसकी अधिकतम क्षमता से केवल एक फीट कम है। पानी का प्रवाह बढ़ने के साथ, रूपनगर प्रशासन ने सतलुज नदी के आसपास के निवासियों को अलर्ट जारी किया है और तुरंत सुरक्षित क्षेत्रों और राहत शिविरों में जाने का आग्रह किया है। पौंग बांध भी अपनी क्षमता से अधिक

हो गया है, जहाँ जलप्रवाह 1.32 लाख क्यूसेक तक पहुँच गया है, जिससे बड़ी मात्रा में पानी छोड़ना पड़ा है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि भाखड़ा से पानी का बहाव 80,000-85,000 क्यूसेक तक बढ़ सकता है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। पंजाब में जारी बाढ़ आपदा ने 14 जिलों में अब तक 43 लोगों की जान ले ली है, जबकि पटानकोट में तीन

लोग लापता हैं। 1.71 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर खड़ी फसलें नष्ट हो गई हैं, जिससे राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है। बाढ़ ने 23 जिलों के 1,902 गाँवों को जलमग्न कर दिया है, जिससे 3.84 लाख से ज्यादा निवासी प्रभावित हुए हैं। आपदा मोचन बलों और स्थानीय प्रशासन ने लगभग 21,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया है। पंजाब में आई विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या बृहस्पतिवार को बढ़कर 43 हो गई, वहीं 1.71 लाख हेक्टेयर में लगी फसलें बर्बाद हो गई हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बृहस्पतिवार को पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया।

उत्तराखंड में हर जिले में वृद्धाश्रम की व्यवस्था होगी: धामी

उत्तराखंड, 05 सितम्बर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के हर जिले में एक-एक वृद्धाश्रम बनाने, दिव्यांगजन से विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 50,000 रुपये करने और कक्षा एक से आठ तक के दिव्यांग छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु आय सीमा समाप्त करने की बृहस्पतिवार को घोषणा की। मुख्यमंत्री ने ये घोषणाएं वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों के साथ संवाद कार्यक्रम के दौरान कीं। इस अवसर पर उन्होंने दिव्यांग शादी अनुदान एवं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के पोर्टल की शुरूआत की और समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत दी जा रही पेंशन की वित्त वर्ष 2025-26 की पांचवीं किस्त का ऑनलाइन भुगतान भी किया। इस मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में एक-एक वृद्धाश्रम की



व्यवस्था की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के सभी जिलों में वृद्धाश्रमों की व्यवस्था को सुदृढ़ कर रही है। उन्होंने कहा फिलहाल बागेश्वर, चमोली और उत्तरकाशी में राजकीय वृद्धाश्रम संचालित हो रहे हैं, जबकि देहरादून, अल्मोड़ा और चंपावत में नए भवन निर्माणाधीन हैं।

इसके अतिरिक्त, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल सहित विभिन्न क्षेत्रों में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित वृद्धाश्रम भी कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य में माता-पिता एवं वरिष्ठ

चीन सीमा विवाद भारत की सबसे बड़ी चुनौती: अनिल चौहान

नई दिल्ली, 05 सितम्बर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने शुक्रवार को कहा कि चीन के साथ भारत का सीमा विवाद देश के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। गोरखपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चीन का सीमा विवाद सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है, वहीं भारत के खिलाफ पाकिस्तान का छद्म युद्ध अगला बड़ा मुद्दा है। उन्होंने आगे कहा कि इस्लामाबाद की रणनीति हमेशा से 'भारत को हजार जख्म देकर लहलुहान करने' की रही है।



विवाद भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और आगे भी रहेगी। दूसरी बड़ी चुनौती पाकिस्तान का भारत के खिलाफ छद्म युद्ध है, जिसकी रणनीति 'भारत को हजार जख्मों से लहलुहान करने' की है। उन्होंने कहा कि एक और चुनौती यह है कि युद्ध के क्षेत्र बदल गए हैं—अब इसमें साइबर और अंतरिक्ष भी शामिल हैं। हमारे दोनों प्रतिद्वंद्वी परमाणु शक्ति संपन्न हैं, और यह तय करना हमेशा एक चुनौती बना रहेगा कि हम उनके खिलाफ किस तरह के

अभियान चलाया चाहते हैं। शीर्ष सैन्य अधिकारी ने मई में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर भी बात की, जिसमें भारत ने 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया था। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों को पूरी तरह से परिचालन की आजादी थी और इसका उद्देश्य हमारे धैर्य की सीमा रेखा खींचना था। उन्होंने कहा, रॉपरेशन सिंदूर के दौरान हमें पूरी तरह से परिचालन की आजादी थी, जिसमें योजना बनाना और लक्ष्यों का चयन भी शामिल था। इसका उद्देश्य आतंकवादी हमले का बदला लेना नहीं, बल्कि हमारे धैर्य की सीमा रेखा खींचना था।

तेलंगाना, 05 सितम्बर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों से आह्वान किया कि वे दोपहर का भोजन छात्रों के साथ करें ताकि भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। रेड्डी ने यहां शिक्षक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें दुख होता है जब सरकारी विद्यालयों में खाद्य विषाक्तता की घटनाएं होती हैं, जबकि सरकार भोजन और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं के लिए धनराशि बढ़ा रही है।

शिक्षा विभाग का भी कार्यभार संभाल रहे रेड्डी ने कहा कि वह विद्यालयों का दौरा भी करेंगे और छात्रों के साथ भोजन करेंगे। उन्होंने कहा, अगर शिक्षक छात्रों के साथ भोजन करेंगे, तो इससे भोजन तैयार करने के उचित मानकों को बनाए रखने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से भोजन की गुणवत्ता और अन्य सुविधाओं में सुधार की



आवश्यकताओं के बारे में सरकार को सूचित करने को कहा। रेड्डी ने कहा कि उनकी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम तरीकों का अध्ययन करने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 200 शिक्षकों को सिंगापुर और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में भेजने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा,

शिक्षकों की योग्यता आमतौर पर निजी विद्यालयों के शिक्षकों से बेहतर होती है।

रेड्डी ने कहा कि राज्य की नयी शिक्षा नीति तैयार करने के लिए पूर्व राज्यसभा सदस्य के केशव राव, विधायक कादियम श्रीहरि और अधिकारियों की एक समिति गठित की गई है।

रेड्डी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सफलता का हवाला देते हुए कहा, उन्हें दूसरे और तीसरे कार्यकाल के लिए मुख्य रूप से शिक्षा में लाए गए बदलावों के कारण चुना गया। उन्होंने शिक्षा को शिक्षकों द्वारा गरीब वर्गों तक सफलतापूर्वक पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को स्वीकार करते हुए कहा, मेरा भी कुछ स्वार्थ है। अगर आप अच्छा काम करेंगे, तो मेरे लिए दूसरे और तीसरे कार्यकाल की संभावना बन सकती है। मैं कुछ भी छिपाना नहीं चाहता। मैं कड़ी मेहनत करूंगा। मैं आपके साथ मिलकर कड़ी मेहनत करूंगा।

त्रिभाषा फॉर्मूला नामंजूर: उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन

तमिलनाडु, 05 सितम्बर। तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने शुक्रवार को दोहराया कि राज्य त्रिभाषा नीति को कभी स्वीकार नहीं करेगा। वह यहाँ अन्ना शताब्दी पुस्तकालय सभागार में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित एक सरकारी समारोह में अध्यक्षीय भाषण दे रहे थे और डॉ. राधाकृष्णन पुरस्कार प्रदान कर रहे थे। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु त्रिभाषा नीति को कभी स्वीकार नहीं करेगा। दो-भाषा प्रणाली पर्याप्त से अधिक है।

त्रिभाषा विवाद ने 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के कार्यान्वयन को लेकर केंद्र और तमिलनाडु सरकार के बीच गतिरोध पैदा कर दिया है। द्रमुक सरकार ने त्रिभाषा नीति को



भगवाकरण नीति करार दिया है जिसका उद्देश्य भारत के विकास के बजाय हिंदी को बढ़ावा देना है। केंद्र ने तमिलनाडु को समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत करोड़ों रुपये की धनराशि रोक दी, क्योंकि राज्य ने एनईपी 2020 के प्रमुख पहलुओं, विशेष रूप से त्रि-भाषा फॉर्मूले को लागू करने से इनकार कर दिया था।

इस साल मई में, तमिलनाडु सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक मूल मुकदमा दायर किया, जिसमें केंद्र पर समग्र शिक्षा योजना के तहत 2000 करोड़ से अधिक की महत्वपूर्ण शिक्षा निधि के अपने वार्षिक हिस्से को रोकने का आरोप लगाया गया था। तमिलनाडु द्वारा एनईपी 2020 के

थे, 'यह शिक्षक का घर है।' आज, वे गर्व से कहते हैं, 'यह डॉक्टर का घर है, यह जज का घर है।' इससे पता चलता है कि शिक्षा ग्रामीण समुदायों में कितनी दूर तक फैल गई है। शिक्षकों के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डालते हुए, उदयनिधि ने कहा, रमध्याह्न भोजन योजना से लेकर सभी विशेष कल्याणकारी कार्यक्रमों तक, इसका श्रेय शिक्षकों को जाता है। खेल मंत्री के रूप में एक विशेष अनुरोध करते हुए, उन्होंने आगे कहा: मैं स्कूली शिक्षकों से अनुरोध करता हूँ कि वे नियमित कक्षाएं संचालित करने के लिए शारीरिक शिक्षा के पीरियड्स का इस्तेमाल न करें। खेलों और शारीरिक प्रशिक्षण को उनका उचित स्थान दिया जाए।

घायल हाथी की इलाज के लिए भुवनेश्वर ले जाने के दौरान मौत

ओडिशा। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में ट्रेन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हुए एक जंगली हाथी की इलाज के लिए भुवनेश्वर ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। वन विभाग के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। यह दुर्घटना बृहस्पतिवार की सुबह राउरकेला वन प्रभाग के सोनाखान और सागरा रेलवे स्टेशनों के बीच हुई। राउरकेला के अनुभागीय वन अधिकारी जशबंत सेठी ने पीटीआई-को बताया, प्रारंभिक उपचार के दौरान पता चला कि हाथी के पिछले दाहिने पैर में चोट लगी थी।



मोहम्मद दानिश
जिला पंचायत सदस्य
वार्ड नं० 10
के भावी प्रत्याशी



NEW LIGHT CLASSES
TRADITION OF EXCELLENCE
2nd Floor, Sheetal Bldg. Near Diamond Talkies, L. T. Road, Borivali (West) Mumbai - 400 092 Maharashtra
ADMISSIONS OPEN
ALL OVER INDIA
ENROLL NOW
SMART CLASSROOM
(ONLINE/OFFLINE)
Courses Offered
● Std. XI & XII (Sci.) ● MHT-CET
● NEET ● Polytechnic & Engg
● JEE (Main & Advance) ● Physics and Maths (ICSE, CBSE, ISC)
M: 9833240148 | E: edu@newlightclasses.com | W: www.newlightclasses.com

जीएसटी का नया दौर: कराधान व्यवस्था क्रांति की ओर



-ललित गर्ग

भारतीय कराधान व्यवस्था में

-ललित गर्ग

जीएफसी काउंसिल की 56वाँ बैठक के बाद घोषित जीएफसी की नई दरें 22 सितंबर से लागू करने करने की घोषणा की गई है। जिसमें अब 12 व 28 फीसदी के दो स्लैब को खत्म करके सिर्फ 5 व 18 फीसदी कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि यह सरकार की ओर से आर्थिक सुधारों की कड़ी में एक नई पहल एवं आयाग है, जिससे जीएफसी को तार्किक बनाने व आम जनता को महंगाई से राहत देने का प्रयास हुआ है। वहीं दूसरी ओर विलासिता आदि वस्तुओं के लिये चालीस फीसदी का एक नया स्लैब जोड़ा गया है। विपक्ष इसे दूर से उठाया गया कदम बता रहा है, तो सरकार आर्थिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम। जीएफसी के बड़े सुधार को लेकर विपक्ष और विशेषतः कांग्रेस एवं भाजपा के बीच जो आरोप-प्रत्यारोप शुरू हुआ है, वह इसलिये औचित्यहीन, अतार्किक एवं व्यर्थ है, क्योंकि जीएफसी परिषद ने लम्बी विवेचना एवं आम सहमतित से यह फैसला लिया है। वहीं कुछ अर्थशास्त्री इस कदम को ट्रंप के टैरिफ वॉर के परिप्रेक्ष्य में उठाया गया सुरक्षात्मक कदम मानते हैं। जिससे घरेलू खपत को बढ़ाकर निर्यात घाटे को कम किया जा सकेगा। वहीं कुछ लोग इसे नवरात्र में दिवाली से पहले सरकार का तोहफा बता रहे हैं।

अनेक कर दरों की जटिलता उपभोक्ताओं के लिए हमेशा भ्रम और बोझ का कारण रही। बार-बार की दर-संशोधन प्रक्रियाओं से व्यापार जगत में असमंजस की स्थिति बनी रहती थी। अब दो स्लेब्स की व्यवस्था से यह समस्या काफ़ी हद तक समाप्त हो जाएगी। उपभोक्ता को वस्तुओं और सेवाओं पर अपेक्षाकृत सरल, न्यायोचित और संतुलित कर ढांचा मिलेगा। इससे न केवल मूल्य स्थिरता आएगी, बल्कि खरीदारी और उपभोग की प्रक्रिया भी सहज होगी। इससे व्यापार एवं उद्योग की विकास की रफ़्तार पकड़ेगी। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। डिजिटलाइजेशन, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, आधार लिंकिंग और पारदर्शी तकने व्यवस्था में विश्वास जगाया है। जीएसटी भी इसी कड़ी का एक क्रांतिकारी सुधार है जिसने ह्राव नेशन, वन टैक्स की अवधारणा को मजबूत किया।

परंतु सच्चाई यह भी है कि जीएसटी विभाग आज भी भ्रष्टाचार की जकड़न से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाया है। छोटे व्यापारियों और उद्यमियों को आज दिन नोटिस, जफ़्त और जटिल प्रक्रियाओं के जाल में उलझाया जाता है। कई बार भ्रष्ट तंत्र इन्हें भयभीत कर अनुचित लाभ उठाता है। यह स्थिति जीएसटी सुधार की भावना के विपरीत है। यदि वास्तव में कराधान को क्रांतिकारी मोड़ देना है, तो जीएसटी व्यवस्था को भी पूर्णतः भ्रष्टाचार मुक्त करना अनिवार्य होगा। यहाँ किसी से छिपा नहीं है कि टेक्स विभाग लंबे समय तक भ्रष्टाचार का गढ़ बना रहा। जटिल कानून और अनेक कर-श्रेणियाँ इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती थीं। लेकिन जब कराधान पारदर्शी और सरल होगा, तो अधिकारी और कारोबारी के बीच की अनावश्यक जटिलता भी कम होगी। इससे जनता एवं छोटे व्यापारियों का विश्वास व्यवस्था पर मजबूत होगा। अब आवश्यकता है कि सरकार जीएसटी प्रणाली को तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर और अधिक पारदर्शी बनाए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल ट्रैकिंग का उपयोग कर चोरी रोकने के साथ-साथ अधिकारियों की मनमानी और रिश्ततखोरी पर भी अंकुश लगाया जा सकता है। करदाता के अधिकारों की रक्षा हो, ईमानदार व्यापारी को भयमुक्त वातावरण मिले और उपभोक्ता को राहत-तभी जीएसटी संचयन क्रांति कहलाएगी। जीएसटी का नया दौर एक बड़ी राहत है और परिवर्तन का संदेश लेकर आया है। अब अगला कदम यह होना चाहिए कि इसे भ्रष्टाचार से पूरी तरह मुक्त कर ईमानदार करदाताओं का विश्वास जीता जाए। तभी यह कहा जा सकेगा कि भारत ने वास्तव में सही अर्थों में एक राष्ट्र, एक कर और एक पारदर्शी कर व्यवस्था की और निर्णायक कदम बढ़ा लिया है।

भारत की आर्थिक यात्रा में कुछ फैसले ऐसे होते हैं, जो केवल नीतिगत बदलाव नहीं, बल्कि युगांतरकारी मोड़ साबित होते हैं। वस्तुएँ एक सेवा कर (जीएसटी) में हालिया सुधार उसी दिशा में उठाया गया एक साहसिक कदम है। कराधान व्यवस्था को सरल बनाने और जनता को सीधी राहत पहुँचाने की दिशा में यह सुधार महज सरकारी निर्णय नहीं, बल्कि एक लोककल्याणकारी दृष्टि का प्रमाण है। आजादी के बाद से भारत में कर-व्यवस्था जटिलताओं, बहुस्तरीय बोज़ और भ्रष्टाचार की दलदल में फँसी रही। छोटे व्यापारी हों या आम उपभोक्ता, हर कोई अप्रत्यक्ष करों की इस भूलभुलैया से परेशान था। मोदी सरकार ने जीएसटी को लागू करके पहले ही इस दिशा में बड़ा कदम उठाया था, लेकिन अब इसे और सरल बनाना तथा दो स्लैब्स तक सीमित करना एक क्रांतिकारी सुधार है। इससे न केवल उपभोक्ताओं पर बोज़ घटेगा, बल्कि व्यवसाय करने की सुगमता भी बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था का असली इंजन जनता की जेब है। जब उपभोक्ता को राहत मिलती है, उसके हाथ में थोड़े अधिक पैसे बचते हैं, तो खर्च बढ़ती है। यही खर्च उद्योगों को गति देती है, उत्पादन में उछाल लाती है और अंततः रोजगार के नए अवसर पैदा करती है। जीएसटी सुधार का सबसे बड़ा असर यही होगा कि यह आर्थिक जीविविधियों को नये पंख देगा और इससे भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थ-व्यवस्था बन सकेगा।

किसी भी लोकतांत्रिक शासन का मूल्यांकन इस बात से होता है कि वह अपने नागरिकों के हितों को किस हद तक प्रार्थमिकता देता है। मोदी सरकार ने जीएसटी सुधार के जरिए यह स्पष्ट किया है कि उनका नीतियाँ महज आँकड़ों का खेल नहीं, बल्कि जनजीवन को आसान बनाने की कोशिश हैं। यह सुधार जनता को केवल आर्थिक ही नहीं, बल्कि मानसिक राहत भी देता है। हालाँकि सुधार के साथ चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं। राज्यों को राजस्व हानि की भरपाई, छोटे कारोबारियों को नई व्यवस्था में सहज बनाना और कर-प्रशासन में पारदर्शिता बनाए रखना, ये सब गंभीर प्रश्न हैं। लेकिन यह इन्हें दूर किया गया तो यह सुधार भारत को एक मजबूत, पारदर्शी और विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था की ओर ले जाएगा। जीएसटी सुधार को जनता के लिए एक उपहार कहना गलत नहीं होगा। यह केवल कराधान का बदलाव नहीं, बल्कि जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की पहल है। यह निर्णय बताता है कि शासन की नीतियाँ केवल सत्ता चलाने के लिए नहीं, बल्कि जनता को राहत देने और देश को विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई हैं। लेकिन यहाँ यह देखना ज्यादा जरूरी है कि इस बदलाव से वास्तव में आम उपभोक्ता को कितना फायदा होता है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उद्योग कर कटौती का लाभ उपभोक्ता कम कैसे पहुँचाते हैं। साथ ही नियामक कितनी सतर्कता से अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।



अशोक भाटिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के लोगों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली में सुधार के रूप में दिया गया दिवाली उपहार, संभवतः तीन स्तंभों - संरचनात्मक सुधार, दारों को युक्तिसंगत बनाना, और जीवन को आसान बनाना - पर आधारित होगा तथा इसमें वर्तमान पांच-दर प्रणाली से दो-दर प्रणाली की ओर बदलाव शामिल हो सकता है। भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर नई दिल्ली के लाल किले से अपने भाषण में श्री मोदी ने कहा था कि सरकार आगामी पीढ़ी के जीएसटी सुधार लाएगी, जिससे आम आदमी पर कर का बोझ कम होगा। यह आपके लिए दिवाली का तोहफा होगा। पीएम मोदी ने दिवाली के जिस गिफ्ट को आम आदमी को देने का वादा किया था, उसे नवरात्र के पहले दिन ही देने की तैयारी की जा रही है। जीएसटी परिषद ने त्योहारी सीजन पर नए जीएसटी ढांचे को लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। परिषद के फैसले से आम लोगों, किसानों और कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी। नई दरें नवरात्र के पहले दिन (22 सितंबर) से लागू होंगी। 22 सितंबर से नए जीएसटी स्लैब को लागू किए जाने के पीछे एक अहम उद्देश्य यह भी है कि 22 सितंबर से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। ऐसे में त्योहारी सीजन में लोग खरीदारी करते हैं। सरकार का

देश भर में सरकार के विज्ञापन अभियान में भी यही कहा गया है। लेकिन यह सच नहीं है। नवतीन करोड़ में कटीती से पहले, वस्तु और सेवा कर के छह चरण थे। शून्य प्रतिशत, 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत, कर 28 प्रतिशत और 40 प्रतिशत अधिक था। इनमें से 12% और 28% को हटा दिया गया। इसका मतलब है कि छह चरणों में से केवल दो चरणों को हटाना जाएगा और अब से चार चरणों में कर लगाया जाएगा। इसमें भी 28 प्रतिशत में से कई 40 प्रतिशत तक चले जाएंगे। केवल एक चरण होना आदर्श वस्तु एवं सेवा कर है। हमारे जैसे देश में, यह असंभव है। हालाँकि, सभी घटकों को अधिकतम दो चरणों में विभाजित करना आवश्यक था। इस संदर्भ में, माल और सेवा कर का मूल मसौदा। विजय केवलकर की समिति ने भी दो चरणों की सिफारिश की थी और कई विशेषज्ञ

अभी भी यही बात कहते हैं। सुधार का दावा करने वाली सरकार ने इससे मुंह मोड़ लिया है। अगर आप इस टैक्स के वास्तविक लाभों का अनुभव करना चाहते हैं, अर्थव्यवस्था के उछाल का अनुभव करना चाहते हैं, तो G. S. T. OX के चरण दो से अधिक नहीं होने चाहिए।

मानना है कि अगर नवरात्र के पहले कुछ लोगों का मानना है कि दिन से छूट का प्रावधान लागू किया भले ही सरकार दो करने का दावा

करती है, लेकिन यह एक धोखा है। विवा मंत्री के बयान में वस्तु-सेवा कर के तीन महत्वपूर्ण घटकों—पेट्रोल, डीजल और शराब को वस्तु-सेवा कर में शामिल करने का उल्लेख नहीं है। अर्थात्, सरकार के पास अभी भी ईंधन की कीमत को छूने की हिम्मत नहीं है, जिस पर परिवहन लागत, जो सभी वस्तुओं/सेवाओं के घटकों की कीमतों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसी स्थिति में, केवल सरकार और विचारकर ही जो हुआ उसे 'प्रमुख सुधार' कह पाएंगे। दूसरों ने कहा कि इन इच्छित सुधारों ने इन इच्छित सुधारों को जन्म दिया है। यह खुश होना वांछनीय है कि सेवा कर में हास्यसायक्य असामंजस्य कुछ हद तक कम हो जाएगा।

यानी 'बन-पाव' पर 5 फीसदी, काजल पर 5 फीसदी, लेकिन बन-मास्क पर 18 फीसदी, जो कई लोगों के नाशते का एक घटक है। या स्कूल स्तर पर आवश्यक टैक्स के दौरान आवश्यक सैनिटरी पैड पर 12 फीसदी और इसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल होने वाले टैम्पोन पर 18 फीसदी। नवीनतम तथ्यांकित सुधारों में चिकित्सा बीमा आदि पर करों में कमी आएगी। बेचारा। अब यह टैक्स फ्री होगा। सबसे बड़ा बदलाव जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर टैक्स में होगा। इन दो आवश्यक सेवाओं पर 18 प्रतिशत का कर लगाना मूल रूप से मूर्खतापूर्ण है। हमारे पास पहले से ही चिकित्सा बीमा चाहने वाले लोगों की एक छोटी संख्या है। इसने इस क्षेत्र की कमर 18 प्रतिशत तक तोड़ दी। यह अब सीधा होना चाहिए। न्यायिक बीमा प्रीमियम पर टैक्स फ्री होगा। वही मूर्खतापूर्ण कर सिनेमाघरों में 'पापकार्न'-नामित

मकके के लट्टे के बारे में था। पहले मकके के लट्टे साधारण होने पर 12 प्रतिशत, नमकौर लट्टे पर 15 प्रतिशत और कारमेलाइज्ड लाठियों पर 18 प्रतिशत कर देना पड़ता था। अब, हम पांच प्रतिशत में सभी लाठियों से छुटकारा पा लेते हैं। अब, सभी लाठियों घटाकर पांच प्रतिशत कर दी जाएंगी। बढ़ते तापमान के कारण, पयर कंडीशनर कोफ़ी विलासिता नहीं है। रेल मंत्रालय का कहना है कि मुंबई में सभी लोकल ट्रेनें वातानुकूलित होनी चाहिए। उपभोक्ता वस्तुएं 5 फीसदी के दायरे में आएंगी। इसमें आपसका स्वागत है।

हालांकि, ये तथाकथित सुधार इस स्वागत को एकमुश्त करने की अनुमति नहीं देते हैं। उदाहरण के लिए, कारों और होटलों के लिए कर संरचना 40 प्रतिशत होगी और 7,500 रुपये से अधिक शुल्क लेने वाली होटल सेवाओं पर भा कर लगेगा। हमारी सरकार को अभी तक पता नहीं है कि ऐसी कार लेने वाले और महंगे होटलों में रहने वाले अमीर नहीं हैं। हमारे पास सड़कों और परिवहन की गुणवत्ता को देखते हुए, बहुत से लोग सुरक्षा कारणों से हाल ही में बड़े-बड़े खरीदते हैं। अब लोग बड़ों की। एक खामी भी है। इसका मतलब है कि 1200 सीसी इंजन की क्षमता वाली कारों पर ज्यादा टैक्स लगेगा, इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि 1150 सीसी क्षमता वाली कारें जल्द ही आएंगी। दूसरा मुद्दा स्टार होटलों का है। यह सच है कि इसका उपयोग अमीरों द्वारा किया जाता है। लेकिन यह भी सच है कि स्टार होटलों में आम होटलों की तुलना में अधिक रोजगार की क्षमता होती है। एक पांच सितारा होटल सीधे कम से कम 500 लोगों को रोजगार देता है और सामान संख्या में अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करता है। इसलिए

ग़रब हम रोज़गार सृजन, खरीदारी और सेवाओं को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, तो हमें बड़ी करों या बड़े होटलों की जरूरत है। ऐसा लगता है कि 'अमीरों को थपड़ मारो' मानसिकता के कारण ऐसा नहीं हो रहा है। सरकार का अगर तब तक सबसे बड़ा आर्थिक सुधार नोटवर्दी रहा है। इसके पीछे मकसद अमीरों की सबक सिखाना था। वास्तव में, किसे फायदा हुआ और कौन दिवालिया हो गया, इसका विश्लेषण ताज़ा है। इस मानसिकता के दोहराव की संभावना है। भारत सरकार की तरफ से GST में किफ़ायत बढ़लाव को लेकर क्रियशुभी क्रेडिट लेने की जुगाड़ में है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपने कई पुराने टवीट सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं कि क्रियशुभी का कहना है कि आठ साल बाद बीजेपी को अपनी गलती का अहसास हुआ है, जबकि क्रियशुभी कहते हैं कि ये ही विरोध कर रही है। क्रियशुभी ने राहुल गांधी ने अपने उन पुराने टवीट शेयर किया, जिनमें उन्होंने लिखा था कि क्रियशुभी 18% CAP के साथ एक रेट के लिए संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी ये काम नहीं करेगी, तो क्रियशुभी करके दिखाएंगी। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसे टवीट शेयर किए जिसमें एक टवीट 8 साल पुराना है और दुसरा 9 साल पुराना है। 2017 में शेयर किए गए टवीट में लिखा था कि भारत को गम्बर सिंह टेक्स नहीं, सरल GST चाहिए। क्रियशुभी और देश की जनता ने लड़कर कई वस्तुओं पर 28% टैक्स खत्म करवाया है। 18% CAP के साथ एक रेट के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अगर भाजपा ये काम नहीं करेगी, तो क्रियशुभी करके दिखाएंगी। वहीं 2016 के टवीट में लिखा था कि

जीएसटी दर पर 18% की सीमा सभी के हित में है।

इस पर पवन खेड़ा ने कहा कि शुरू से राहुल जी 2 स्लैब्स की बात कर रहे हैं। एक सिप्लिफिकेशन होना चाहिए। हमारी सलाह मानने में 9 साल लग गए। वाकई इनकी समझ कम है या घमंड है। कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने कहा कि मैं आठ साल बाद सरकार को अपनी गलती का एहसास होने पर उसकी सराहना करता हूँ। उन्होंने कहा कि आठ साल तक बीजेपी ने मध्यम वर्ग और गरीबों को निचोड़ा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि उस समय हमने सरकार दी थी कि ऐसा कर नहीं लगाया जाना चाहिए, लेकिन उस समय न तो प्रधानमंत्री और न ही मंत्रियों ने हमारी बात सुनी। उन्होंने कहा कि मैंने संसद में भी आवाज उठाई लेकिन उन्हें फायदा नहीं हुआ। चिदंबरम ने कहा कि GST की दरें 12% और 18% से घटाकर घटाकर 5% कर दी गई हैं। कांग्रेस नेता जयराम रेग्मी ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि कांग्रेस लंबे समय से जीएसटी 2.0 की वाकालत करती रही है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक से पहले पीएम मोदी ने 15 अगस्त को जीएसटी की दरों को घटाने की बात कही थी। उन्होंने बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या जीएसटी परिषद अब केवल एक औपचारिकता बनकर रह गई है? कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम को कांग्रेस ने 2017 में भी ध्यान दिनाय कि उनके द्वारा लिया गया निर्णय गलत है। उन्होंने कहा कि इसे इसे मुकद्दम एंड सिंपल टैक्स कहा गया था, लेकिन यह ग़ोथ स्प्रेडिंग टैक्स साबित हुआ। अब यह तो धीरे-धीरे ही पता चलने का आम जनता को दिवाली ला तालिका गिफ्ट मिला है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर जीएसटी सुधार के वायदे को किया पूरा

सैंधवा में अनंत चतुर्थी के चल समारोह का गौरव पूर्ण इतिहास



-नरेंद्र तिवारी 'पत्रकार'

संधवा बड़वानी जिले के सबसे बड़े शहर संधवा में गणेश उत्सव इतिहास काफ़ी पुराना है। यह उत्सव शहर और क्षेत्र के निवासियों का सबसे बड़ा सांस्कृतिक उत्सव बन गया है। शनिवार की रातभर शहर की सड़कों पर झिलमिलाती झांकियों का काफ़िला ढोल ताशो और डीजे की धुन पर थिरकने को तैयार रहेगा। समय के साथ उत्सव में काफ़ी बदलाव होते जा रहे हैं अर्न्त चतुर्थी का यह चल समारोह शहर के कलाकारों, करतबबाजों, पहलवानों को अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर प्रदान करता था। गणेश उत्सव और चल समारोह ने शहर के कई नामी लोगों के नाम को रोशन किया।

शहर के 74 वर्षीय सामजिक कार्यकर्ता बद्री प्रसाद शर्मा के अनुसार सेंधवा में गणेश उत्सव की

शुरूवात काफी पुरानी है उनकी स्मृति के अनुसार 1960 में रामचंद्र मुकरदम ने गणेश प्रतिमा की स्थापना की थी। उन्होंने बैलगाड़ी पर सजा कर अनेक चतुर्थी को विसर्जन किया था। इसी दौरान भीमराव लाडने नेम नामक व्यक्ति ने मोतीबाग चौराहे के दाजीजी भवन पर गणपति जी को वाहन मुसक पर विराजित कर शिव-पार्वती की प्रतिक्रमा की झांकी का प्रदर्शन किया था। बकौल बंदीप्रसाद शर्मा शहर के सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल की यह शुरूवात मानी जा सकती है। महाराष्ट्र से सटा और इंदौर से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस शहर में इन दोनों ही स्थानों से संस्कृति का प्रभाव पड़ा। इंदौर में मीलों द्वारा चलित झाँकियायें निकालने की परम्परा से प्रभावित यह शहर की तत्कालीन गड्डे वाली जिनिंग (सत्यम कोटेक्स) के मालिक बसंत अग्रवाल द्वारा स्थानीय जिनिंग मजदूरों एवं व्यापारियों के सहयोग से वर्ष 1961 से नियमित चलित झाँकी की शुरूवात की जो कुछ बरसों तक चलती रही। इस परम्परा को तले खेमराज सेठ मितल ने अपनाने हाथों में लिया। हिन्दुसमाज सेवा संगठन अपनी झाँकी में धार्मिक हथ्यों का चित्रण करता था। खेमराज सेठ मितल के पुत्र मुकेश

मिमतल के अनुसार करीब 70 के दसक में उनुके पैता ने हिन्दू समाज से बसा संगठन के बनाव ले चलित झिकियों की आरम्भ किया। झिकियों के निर्माण के लिए नागलवाड़ी के प्रसिद्ध मुर्तिकार उत्तम राठौड़ झिकियों के लिए मुर्तियों का निर्माण करते थे। धामनोद के मांगीलाल पेंतर कलर एंव ब्रश से बैक ग्राउंड बनाते थे। इक बार पुकर विमान लम्बे चेसीस पर बना दिया गया जिसके शहर के मुख्य मार्गों से निकलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

झंझिकियों को इस परम्परा में महाराष्ट्र समाज सेवा संगठन का उदय भी लगभग इसी समय का है। इस संगठन के कलाकार आर्थिक तंगी के दौर में अपने हाथों से मूर्तियाँ, पोस्टर और झंझिकियों को सजाने का कार्य करते थे, इस संगठन द्वारा शहर में कलात्मक झंझिकियों का प्रदर्शन लम्बे दौर तक किया गया। शुरूवाती दौर में यहाँ हमें सर जो स्वयं इक अघ्यापाक कोकरा भी इस झ्झांकी के लिए पेंटिंग करते थे, गोविन्द पेंटर भी इसी संगठन की देन है जो पेशे से चालक थे किंतु अनंत चतुर्थी का चलत झांकी निर्माण के लिए कामकाज छोड़ झांकी निर्माण में जुट जाते थे। हैरी चौधरी, हिमामन वारुले, अण्णा, बाप्पू डैनी प्रकाश निकुम्भ, पुरुषोत्तम रावल भी झंझिकियों में महती भूमिका निभाते

थे। गोविन्द शर्मा अपनी जोशीली आवाज़ में महाराष्ट्र समाज सेवा संगठन की झांकी प्रस्तुतीकरण करते थे। वर्ष 1984 में बनी कालका माता की झांकी आज भी शहर के लोगो याद है। पालीवाल समाज सेवा संगठन की इस कड़ी में जुड़ा जिन्होंने चलिता और स्थायी झांकियों का मिलसिला मिल्नम्बे समय तक जारी रखा। इस कट्टी में जय भवानी एकता संगठन का 1980 दशक में खासे जोरजोश के साथ उतरा जिन्होंने सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल में स्थानीय कलाकारों एवं बाहर से बुलाई चलिता झांकियों का निर्माण किया। शंकर सेनी, जयस कौमन, सुभाष मित्तल, काठू काकामदार, बंसीलाल ठाकरे, मुकेश अग्रवाल सहित अनेको कार्यकर्ता झांकी निर्माण में महती भूमिका निभाते थे। दिनेश गंज दाहा गोदाम एकता संगठन जो अब निमाड़ का सबसे बड़ा गणेश उत्सव पांडाल विगत बरसो से बना रहा है। चलिता झांकियों में भी भाग लेता था। रमू काका, घनश्याम शर्मा, गुल्लि शर्मा, संजय यादव दिनेश गंज की चलिता झांकी का प्रतिनिधित्व करते थे। महाराज गुरू एकता संगठन, युवा हिन्दू समाज सेवा संगठन, जवाहर गंज मित्र मंडल, आजाद नुकड़ड़, प्रेस नुकड़ड़ मोतिबाग की समयके के साथ

उभरने वाले गणेश मंडल है ब्रद्री प्रसाद शर्मा के अनुसार चल समारोह 1969 त मीलाना अजाद मार्ग से होता हुआ एबी रोड, गुरुद्वारा मार्ग पर पहुँचता था। किसी भी धार्मिक स्थानों को ढकने की परम्परा नहीं थी। गुलाल का प्रचलन नहीं था। स्थानीय क्लबाकारों के ढप (चमड़े से बना बाजा) बजते थे उसी पर लालिया घुमाई जाती थी अन्य करतब किसी जाते थे। अखाड़े सभी संगठन के होते थे। खेमारजा सेठ साईकिल से प्रदर्शन करते थे। पुरेशा नुसली जो पेशे से चालक थे नुसली शहर के चल समारोह में नान चाकू के प्रदर्शन की शुरूवात की थी। मोहन गुर्जर दाँतो से साईकिल घुमाने का करतब दिखाते थे। गणेश उत्सव आरम्भ होने के पूर्व अखाड़े अपनी तैयारियां शुरू कर देते थे जिस संगठन का अखाड़ा अव्वल एवं श्रेष्ठ प्रदर्शन करता शहर में उनका नाम होता था। समय के सजा खावाड़ों का लोप होता जा रहा है। गुलाल उड़ाने में प्रचलन बढ़ने से चल समारोह में रूचि कम हो गयी है। डीजे पर फुहड नचना ने भी सांस्कृतिक उत्सव महत्ता को कमजोर किया है। शहर का गणेश उत्सव काफी चर्च से इस उत्सव से जुड़े अच्छे बुर्चे अनुभव शहर ने भोगे हैं अब भी यह उत्सव शहर का सबसे बड़ा

सांस्कृतिक उत्सव है। वर्तमान में जहाँ 10 दिवसीय गणेश उत्सव की परम्परा को दिनेशगंज एकता संगठन संजय यादव के नेतृत्व में विशाल पांडाल के निर्माण के साथ इस परम्परा बखूबी निवाह करता आ रहा है। 16 सितम्बर 2025 को शहर में 25 से अधिक झाँकिया धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों के साथ चली समारोह का हिस्सा बनने जा रही है। बरमुडा अखाड़ा एवं अम्बेडर युवा शक्ति अखाड़ा अपना शानदार करतबों की प्रस्तुति देगा। वहीं श्रीराम मित्र मंडल पुराना बस स्टैंड इक लौटा जल सभी समस्याओं का हल, मौसम चौराहा एकता संगठन संभाजी महाराज, विकास आर्य मित्र मंडल नर्मदा मैया, सालासर बालाजी मित्र मंडल महाकाल मंदिर उज्जैन, जय भवानी मित्र मंडल मिशन सिंदूर, बागेश्वर साकार मित्र मंडल प्रेमानंद महाराज, संतोषी माता मित्र मंडल लव जिहाद, जवाहर गंज मित्र मंडल कृष्ण लीला, आजाद नुककड़ कृष्ण लीला, विवेक तिवारी मित्र मंडल सीताहरण, किला रोड मित्र मंडल छावा फिल्म, हरि सिद्धि गणेश मंडल रामेश्वरम, जोगवाड़ा रोड मित्र मंडल राम केवट विषय पर झाँकियां प्रस्तुत करने का रहे है। अनंत चतुर्थी का उत्सव हमारी सांस्कृतिक परम्परा को मजबूत करने का अवसर है।

6 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस

अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, जिसका उद्देश्य गिद्धों की सभी समस्याओं का प्रतिबिम्ब और उनकी घटती संख्या के बारे में जागरूकता पैदा करना है। 2009 में दक्षिण अफ्रीका के बडुस ऑफ प्रे कार्यक्रम और यूनाइटेड किंगडम के हॉक कंजरवेंसी ट्रस्ट के सहयोग से शुरू किया गया था। तब से, प्रकृति प्रेमी गिद्धों की घटती संख्या को देखते हुए, सितंबर के पहले शनिवार को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश में हर स्तर पर प्रदूषण दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। आधुनिक उपकरणों, कारखानों, वनों की कटाई, परमाणु परीक्षण, गोला-बारूद, बढ़ते हुए गिद्ध जैसे हालात और बढ़ते औद्योगीकरण के कारण आकाश-पाताल- पूर्व-पश्चिम-उत्तर-दक्षिण-पृथ्वी-प्रकृति पूरी तरह से अलट-बिखर स्थिति में आ गई है। इसके कारण, हर जगह भारी मात्रा में प्रदूषण देखने को मिलता है। यही परिणाम आज मनुष्य, पशु-पक्षी और सभी जीव-जंतु भुगत रहे हैं। आज बढ़ती प्रदूषण के कारण पक्षियों की आकाश में उड़ान भरने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वनों की कटाई

के कारण जंगल में जानवरों का जीवन रहना बहुत कठिन हो गया है। और अब प्रकृति प्रेमी प्रेक्ष, जो प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं, आज मौत के मुंह में जा रहे हैं। इसे बहुत ही भयावह स्थिति कहा जा सकता है। गिद्ध मुख्य रूप से मृत जानवरों का मांस खाकर प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए, गिद्धों ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई है और प्रकृति को स्वस्थ रखते हुए पृथ्वी, मानवता और सभी जीवित प्राणियों को रक्षा की है। लेकिन भारत के लिए चीकाने वाली खबर यह है कि भारत में गिद्धों की संख्या में 90 प्रतिशत की कमी आई है, जो दशार्ता है कि भारतीय प्रकृति बहुत बड़े खतरे में पड़ गई है। इसके लिए आज की स्थिति में गिद्धों को बचाना समय की मांग है। गिद्धों को मौत के मुँह में धकेलने का काम स्वयं मानवता ने किया है। भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियाँ हैं, जिनमें से 6 भारतीय और 3 प्रवासी हैं। 1980 के दशक तक देश में गिद्धों की संख्या 4 करोड़ थी, लेकिन, डाइक्लोफेनाक जैसी जहरीली दवाओं के कारण सिर्फ 15-20 सालों में ही

90 प्रतिशत गिद्ध मर गए कुछ प्रजातियाँ तो विप्लव होने के कारण पर हैं। जानवरों के दी जाने वाली डाइक्लोफेनाक दवा गिद्धों की मौत का कारण बन गई है। इसी के चलते सरकार ने 2006 में डाइक्लोफेनाक दवा पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालाँकि, चूँकि इस दवा का इस्तेमाल अब भी हो रहा है, इसलिए भारत सरकार ने 2015 में इसके उत्पादन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। हालाँकि डाइक्लोफेनाक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन जानवरों पर दूसरी नॉन-स्टेरॉइडल एंटी-इंफ्लेमेटरी दवाओं का इस्तेमाल होता है और इस दवा का इस्तेमाल है। यानी हम जानवरों को खतरा पैदा है, वो सभी गिद्धों की मौत का कारण बन रही हैं। इसलिए, समग्र आँख है कि मरें हुए जानवरों का मांस खाकर प्रकृति के संतुलन को दुर्बल रखने वाले प्रकृति के मित्र को बचाया जाए। 25-30 साल पहले मरें हुए जानवरों का मांस गिद्धों के लिए पौष्टिक और पोषक होता था। लेकिन आधुनिक युग में पिछले कुछ सालों में जानवरों को कई तरह की दवाइयाँ और इंजेक्शन देकर उन्हें कई बीमारियाँ से बचाया गया है। कुछ

जानवरों में प्रजनन और दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए बड़ी मात्रा में दवाइयों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन प्रकृति की रक्षा करने वाले गिद्धों पर इसका उल्टा असर हो रहा है। क्योंकि जानवरों की मरने के बाद जहरीली हो जाती हैं। इन मरे हुए जानवरों को गिद्ध खा जाते हैं और कभी बीमारियाँ से ग्रस्त होकर उन्हें मौत से जूझना पड़ता है। इस वजह से प्रकृति के मित्र गिद्धों की संख्या में 90 फीसदी की कमी आई है। यह बेबंद चित्ताजनक और गंभीर मामला है। एक जानकारी के अनुसार 1993 से 2007 के बीच सफेद चोच वाले गिद्धों जो कि एक भारतीय प्रजाति है, उनकी संख्या 99.9 फीसदी तक खत्म हो गई है अर्थात गिद्धों की संख्या में कमी प्रकृति की रक्षा की दृष्टि से अत्यंत चिंताजनक विषय है। इसके कारण गिद्धों की अविधेक्ष प्रकृति के विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है; प्रकृति के भारतीय मित्र को बचाना समय की मांग है। भारत में 2020 से 2025 तक गिद्ध संरक्षण की कार्ययोजना के अनुसार, महाराष्ट्र, वन विभाग, भारतीय गिद्ध फाउंडेशन के साथ मिलकर गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र

स्थापित करने का प्रयास करने जा रहा है। मैं इसका स्वागत करता हूँ, जो अत्यंत हर्ष का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस के अवसर पर, भारत सरकार प्रकृति-मित्र गिद्धों को बचाने के लिए प्रयास करने चाहिए, और साथ ही, संपूर्ण राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों के वन विभागों को गिद्धों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करने की तत्काल आवश्यकता है। इससे प्रकृति को

न्यू बूगी वूगी अकेडमी के बच्चों ने शिक्षक दिवस पर किया कार्यक्रम का आयोजन

पटना। न्यू बूगी वूगी अकेडमी द्वारा शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सिन्हा लाइब्रेरी रोड स्थित अर्दित कम्प्युनिटी हॉल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्थान के बच्चों ने अपनी रंगारंग प्रस्तुतियों और नृत्य कला का प्रदर्शन कर शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि बच्चों की माताओं ने भी मंच पर अपनी प्रस्तुतियों से शिक्षकों के प्रति स्नेह और सम्मान प्रदर्त किया। बच्चों और अभिभावकों के इस साझा प्रदर्शन ने उपस्थित लोगों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम आयोजक एवं न्यू बूगी वूगी अकेडमी के निदेशक अनिल राय ने कहा कि आज का यह कार्यक्रम समाज के निष्ठा प्रदान करने की समर्पित है। शिक्षक ही वह प्रकाश पुंज हैं जो बच्चों के जीवन को दिशा प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक दिवस हमें यह याद दिलाता है कि शिक्षा ही सबसे बड़ा धन है। आज के बच्चों ने जिस उत्साह से कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, वह निश्चित रूप से प्रेरणादायक है। वहीं संस्थान के शिक्षकों ने भावुक होते हुए कहा कि छात्रों और अभिभावकों का यह सम्मान हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है।

जीवित बने रहने में बहुत मदद मिलेगी और साथ ही, हम प्रदूषण पर काबू पाने में भी सफल होंगे। सभी को यह याद रखना चाहिए कि अगर जंगल सुरक्षित है, तो प्रकृति सुरक्षित है, प्रकृति सुरक्षित है, जानवर सुरक्षित हैं और जानवर सुरक्षित हैं, तो हम सब सुरक्षित हैं। क्योंकि मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है। इसलिए प्रकृति-मित्र गिद्धों को बचाने के लिए युद्धस्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए।

न्यू बूगी वूगी अकेडमी के बच्चों ने शिक्षक दिवस पर किया कार्यक्रम का आयोजन

पटना। न्यू बूगी वूगी अकेडमी द्वारा शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सिन्हा लाइब्रेरी रोड स्थित अदिति कम्युनिटी हॉल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्थान के बच्चों ने अपनी रंगारंग प्रस्तुतियों और नृत्य कौशल का प्रदर्शन कर शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि बच्चों की माताओं ने भी मंच पर अपनी प्रस्तुतियों से शिक्षकों के प्रति स्नेह और सम्मान प्रकट किया। बच्चों और अभिभावकों के इस साझा प्रदर्शन ने उपस्थित लोगों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम आयोजक एवं न्यू बूगी वूगी अकेडमी के निदेशक अनिल राज ने कहा कि आज का यह कार्यक्रम समाज के निमार्ता शिक्षकों को समर्पित है। शिक्षक ही वह प्रकाश पुंज हैं जो बच्चों के जीवन को दिशा प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक दिवस हमें यह याद दिलाता है कि शिक्षा ही सबसे बड़ा धन है। आज के बच्चों ने निज उस्ताह से कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, वह निश्चित रूप से प्रेरणादायक है। वहीं संस्थान के शिक्षकों ने भावुक होते हुए कहा कि छात्रों और अभिभावकों का यह सम्मान हमारे लिए सबसे बड़ी पूजा है।



नोबल हॉस्पिटल & रिसर्च सेन्टर
नोबल हास्पिटल اینڈ ریسرچ سنٹر

डा. शारिक नदीम
M.B.B.S., MD
FICC (Cardiology)
फिजियन, हृदय
एवं मधुमेह रोग विशेषज्ञ

डा. अभिजीत कुमार
M.B.B.S., M.I.M.A
जनरल फिजियन

◆ शुगर की जाँच

◆ HbA1c की जाँच

◆ हड्डी की जाँच (BMD)

◆ नस की जाँच (Neuropathy)

◆ फेफड़ों की जाँच (Spirometry)

◆ यूरिक एसिड

◆ कोलेस्ट्रॉल की जाँच

◆ थायरॉइड की जाँच

Helpline- 6307493268

डा. डी.ए.ए. अहमद
B.U.M.S.CCH (Indore)
N.D.E.P.C.

आजमगढ़ रोड, निकट- सेण्ट पैट्रिक स्कूल, पचहटियाँ, जौनपुर- 222001

जीवन रक्षा हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर



डा0 नवीन कुमार सिंह
M.B.B.S., M.S. (Ortho)
हड्डी व जोड़ु रोग विशेषज्ञ



डा0 शिल्पी सिंह
M.B.B.S., M.S. (Obs & Gyn)
स्त्री रोग विशेषज्ञ



- फ्रैक्चर
- गठिया
- कमर दर्द
- ऑथराइटिस
- कूल्हा, घुटना प्रत्यारोपण
- इत्यादि रोगों का इलाज



- सिजेरियन डिलीवरी
- बच्चेदानी का ऑपरेशन
- द्यूमर का ऑपरेशन
- दूरबीन विधि द्वारा
- बच्चे की जाँच
- नार्मल डिलीवरी



आयुष्मान कार्ड द्वारा निःशुल्क इलाज की सुविधाएं
इमरजेन्सी सुविधा 24 घण्टे उपलब्ध
नवा पता- पुनिस चौकी के सामने, सिपाह, आजमगढ़ रोड, जौनपुर (उ०.प्र०) ☎ 6390303050



त्रिभुवन सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल



डा0 सृहा सिंह
M.B.B.S., MD (Pt. JNM Raipur)
CCEBDM (Diabetics)
जनरल फिजिशियन एवं मधुरोग विशेषज्ञ
पूर्व चिकित्सक आपोलो हॉस्पिटल, हैदराबाद



डा0 जयेश सिंह
एम.बी.बी.एस., एम.डी. (पीडियाट्रिक्स)
डॉ.एम. (नियोनेटोलॉजी)
(Fernandez Hospital, Hyderabad)
DASSI (KEM Pune)
ONTOP (AIIMS New Delhi)

- पूर्विल के प्रथम व एकमात्र सुपर स्पेशलिस्ट नवजात शिशु व बाल रोग विशेषज्ञ**
- नवजात शिशु का आई.सी.यू. एवं बच्चों के सभी रोगों का इलाज।
 - निमोनिया, जन्म पर गन्दा पानी पीने वाले नवजात अत्याधुनिक आई.सी.यू. की सुविधा।
 - समय से पूर्व (सतवासे) में पैदा हुए बच्चों का इलाज एवं बच्चों का समस्त टीकाकरण।
 - हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड के द्वारा नवजात शिशु व बच्चों के डायलिसिस की सुविधा
 - निशुल्क उपलब्ध है।
 - इत्यादि समस्त रोगों का इलाज की सुविधा।
- हृदय रोग एवं डायबटीज रोग विशेषज्ञ**
- वयस्क में हार्ट, किडनी, शुगर, पेट रोग, लकवा, पैरालाइसिस, निमोनिया,
 - लीवर, डेंगू, मलेरिया, टाईफाइड, अस्थमा/दमा, हाईब्लड प्रेशर, मलेरिया,
 - डायलिसिस, सिजेरियन डिलिवरी, नर्सों में शुनूपन, मस्तिष्क ज्वर, पीलिया,
 - हेपेटाइटिस बी, ल्यूकोरिया, खूनी पेचिस, सर दर्द, माइग्रेन, यूरिन इन्फेक्शन
 - स्वास् व फेफड़ा रोग व अन्य सभी रोगों का इलाज किया जाता है।

आयुष्मान कार्ड द्वारा निःशुल्क इलाज की सुविधाएं
पता- दिवानी कचहरी, अम्बेडकर तिराहा, जौनपुर (उ०.प्र०)
☎ 05452-356274/ 7992031213, 9026551423



अरुणोदय सर्जिकल एण्ड ट्रामा सेन्टर



डा. अरुण आर. सिंह
कन्सल्टेंट लैप्रोस्कोपिक सर्जन
(एच.एम.ओ.) एच.टी.एम.एम.जी.एच. (आफ़ हॉस्पिटल मुंबई)
एम.आर. जम. गौतम चिकित्सक जेनरल हॉस्पिटल (राज्य मुख्यालय)
राज्य-822945 (एच.एम.ओ.)

जनरल सर्जरी
स्त्री एवं प्रसूति रोग
आर्थोपेडिक (सर्जरी एवं परामर्श)
क्रीमोबिरेपी सुविधा उपलब्ध
न्यूरो सर्जरी (परामर्श एवं सर्जरी)

वेंटिलेटर एवं डायलिसिस
की सुविधा उपलब्ध
प्रसिद्धि डाक्टर स्टाफ तथा सभी मानकों पर खरा
उतरने वाला जनपद का एक मात्र हॉस्पिटल
दूरबीन विधि द्वारा सभी प्रकार की सर्जरी
जनरल मेडिसिन, मधुमेह रोग

गर्बा एवं मृत रोग (सर्जरी एवं परामर्श)
गैस्ट्रोइन्टेरोलॉजी (ड्रगडोस्कोपी एवं
कालोनोस्कोपी)
एक्सीडेंटल एवं ट्रामा इमरजेन्सी
सेवा 24 घण्टे उपलब्ध

डा0 पुनीत सिंह
M.S., M.C.H.
गुर्ला गढ़ पुर रोग विशेषज्ञ (एच.एम.ओ.)

डा0 रवि प्रकाश सिंह
M.S. (Ortho)
हड्डी एवं जोड़ु रोग विशेषज्ञ

डा0 प्रभात सिंह
M.D. (Medicine)
आंतरिक रोग विशेषज्ञ

डा0 सुमित कुमार सिंह
M.D. (Neuro Psychiatrist)
न्यूरोलॉजिस्ट रोग विशेषज्ञ



बीमा कार्ड धारकों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध
आयुष्मान कार्ड द्वारा निःशुल्क इलाज की सुविधाएं
☎ 8090966086, 8090015086
कलीचाबाद, जौनपुर



SALVATION HOSPITAL साल्वेशन हॉस्पिटल



डॉ. प्रियंका श्रीवास्तव
B.A.M.S.
(स्त्री रोग विशेषज्ञ)

पंडित दीनदयाल उपाध्याय
राज्यकर्मी केशलेस चिकित्सा योजना
संबद्ध अस्पताल

**आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री
जन आरोग्य योजना**
के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पताल
प्रदेश के लगभग 6 करोड़ लोगों के लिए 5 लाख करोड़ तक के स्वास्थ्य खर्च को पूरा करे में सक्षम



डॉ. विवेक श्रीवास्तव
M.D. (Physician, F.G.O.)
(APOLO HOSPITAL) P.G.D.S.
Member of Indian Medical
Association UPMCI Reg. No. 95653



आई.सी.यू. डायलिसिस एच.डी.यू.
नेत्र विभाग | अस्थि रोग विभाग
दन्त चिकित्सा | किडनी विभाग
जनरल मेडिसिन | जनरल सर्जरी

नोट- प्रत्येक महीने के दूसरे रविवार को प्रयागराज के गुर्दा रोग विशेषज्ञ डा0 सन्तोष मोर्य (M.D., D.M. Nephro) 12 बजे से 4 बजे तक उपलब्ध रहते हैं।
कंधरपुर, मुरादगंज, जौनपुर (वाराणसी-लखनऊ न्यू हाइवे के बगल में बाईपास से 400 मीटर की दूरी पर) ☎ 9138828282, 8686867547



एस.आर.एस. हॉस्पिटल एण्ड ट्रामा सेन्टर



डा. अभय प्रताप सिंह
MBBS (KGMU), DNB (Ortho), MS (Ortho)
UCN, FLJR (Germany), MNAMS
आर्थोस्कोपिक एण्ड ज्वाइंट
रिप्लेसमेंट आर्थोपेडिक सर्जन
हड्डी रोग विशेषज्ञ
ओ.पी.डी. प्रतिदिन



डा. आनन्द त्रिपाठी
MBBS, MD, DM (Neuro)
क्यूरेटिविजियन
ओ.पी.डी. प्रतिदिन



डा. निदा सलाम
CBO
स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ
ओ.पी.डी. प्रतिदिन



डा. अरविन्द कुमार अग्रहारी
MBBS, MS, MCh (Neuro)
क्यूरेटिविजियन
विजिटिंग/ऑन काल



डा. एस.के. मिश्रा
MBBS, MS (General Surgeon)
जनरल सर्जरी
विजिटिंग/ऑन काल



डा. पंचला मिश्रा
MBBS, MS (Obs & Gyn.)
स्त्री रोग विशेषज्ञ
विजिटिंग/ऑन काल



डा. राजेश त्रिपाठी
MBBS, MD (Anesthesia)
एनेस्थीसिस्ट रोग विशेषज्ञ
विजिटिंग/ऑन काल



7355 358194



05452- 356555

तेज डायग्नोस्टिक सेन्टर के सामने (पेट्रोल पम्प के बगल में) नईगंज तिराहा, जौनपुर



ए. एम. बजान



मो. अशहद



अब्दुल माजिद

१ मानी कलां, गुरैनी रोड, जौनपुर- 222139 ☎ 9621032024, 9651316060, 9621139686

AMIR TRAVELS

Hajj & Umrah Services
DOMESTIC & INTERNATIONAL
AIR TICKETS

Visit Visa, Holiday Tour Packages, Waqala Delhi & Mumbai Gamca & Medical Services
Emigration, Visa Stamping, Currency Exchange, Money Transfer



- Withdrawal & Deposit Money From All (atm & Adhar Services)
- Passport, Pan Card & Driving License Services
- Common Services Center (csc) & Sahaj Jan Seva
- Kendra Related Services ☎ 7860303530, 9616636079

प्रो०- मो० आसिफ सिद्दीकी संवाददाता गुरैनी, मानीकलां

सह- संपादक डॉ. इम्तियाज अहमद सिद्दीकी (उर्फ बाबू भाई) उत्तरशक्ति हिंदी दैनिक, जौनपुर-लखनऊ (उत्तर प्रदेश)



निकट- नसीराबाद चौक, पूर्व प्रधान नेयाज़ अहमद कटरा, मानीकलां, जौनपुर (उ० प्र०)